(b) what remedial steps have been taken by Government in this regard; and

(c) what is the number of complaints received with regard to the implementation of the National Rural Employment Programme and what action has been taken by Government on them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHAR THAKUR): (a) and (b) National Rural Employment Programme (NREP) which was being implemented in all the States including that of Gujarat has been merged into a new programme known as Jawahar Rozgar Yojana. (JRY) from the year 1989-90. The progress under the Yojana is monitored in terms of employment generated in mandays. Against the employment generation targets of 244.25 lakh mandays fixed for Gujarat under JRY for the year 1991-92, 254.13 lakh mandays have been generated. Since the prescribed target has been achieved, the question of taking remedial steps does not arise.

(c) During the period 1991-92, no complaints regarding mis-appropriation of JRY funds and improper implementation of Yojana in Gujarat was received in the Ministry.

गुजरात में बंजर भूमि क्षेत्र

3078. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में जिलेवार बंजर भूमि का क्षेत्र कितना-कितना है ;

(ख) बंजर भूमि के कुल कितने क्षेत्र को हरित क्षेत्र में बदला जा सकता है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य के कुल कितने क्षेत्र में वनरोपण किया गया है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने क्षेत्र को वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत लाए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) और (ख) गुजरात में बंजर भूमि का पता लगाने के लिए अभी कोई विस्तृत जिलावार सर्वेक्षण नहीं किया गया है लेकिन एक अनुमान के अनुसार, गुजरात में कुल 78.36 लाख हैक्टेयर बंजर भूमि है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में वनरोपण/वृक्षारोपण कार्य के अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र निम्न प्रकार है :—

वर्ष	वनरोपण/वृक्षारोपण (लाख हैक्टेयर में)	निजी भूमि पर वृक्षारोपण हेतु पौधों का वितरण (संख्या लाख में)
1989-90	1.95	*
1990-91	0.485	2356.36
1991-92	0.63	2511.86

* निजी भूमि पर वृक्षारोपण हेतु पौध के वितरण के लिए अलग से लक्ष्य केवल 1990-91 से ही दर्शाए गए थे।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनरोपण तथा वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं के तहत निधियों की उपलब्धता के अनुसार वर्ष दर-वर्ष के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए, गुजरात में वनरोपण तथा वृक्षारोपण और पौध वितरण के अन्तर्गत 1992-93 के लिए लक्ष्य नीचे दर्शाए गए हैं :—

(1) पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षा रोपण हेतु) (लाख में) 2500.00

(2) क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि) (हैक्टेयर में) 70,000.00

उत्तर प्रदेश में गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना

3079. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1000 से 1500 तक की आबादी वाले 50 प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ने की परिकल्पना की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत अभी तक उत्तर प्रदेश में जिलेवार कितने गांवों को सड़क से जोड़ा गया है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिलेवार निर्धारित लक्ष्य क्या था ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना के अंतर्गत सड़कों से जोड़े गए गांवों की जिलावार संख्या के बारे में सूचना नहीं रखता है ।

(ग) चूंकि ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य का विषय है, अतः केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता

3080. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर (ठाकुर) : (क) जी नहीं । तथापि, जवाहर रोजगार योजना के आबंटन की 6 प्रतिशत निधियां इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु निर्धारित की जाती हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में स्वयंसेवी संगठनों के लिये सहायता

3081. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में स्वयंसेवी संगठन को लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद के माध्यम से कोई सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन से संगठनों को यह सहायता प्रदान की गई और प्रत्येक संगठन को कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकरण की कोई समीक्षा नहीं की गई है जिसके फलस्वरूप लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पायी ; और